हिमाचल का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक समाचार पत्र

आप का सामना

हक़ीक़त से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब,चंडीगढ़,दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि.नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-23 शिमला शुक्रवार,22 ls 28 ekpZ 2024 आरएनआई एचपीएचआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 रू०

मंडी संसदीय सीट पर प्रतिभा सिंह ने चुनाव लडने़ से किया इन्कार

vkd lk f'keykA सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वह मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बचाने को उपचुनाव में जीत जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वह मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बचाने को उपचुनाव में जीत जरूरी है। बुधवार सुबह नई दिल्ली से शिमला लौटीं प्रतिभा बोलीं, अगर मैं मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ती हूं तो विधानसभा क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे सकूंगी। जिस भी प्रत्याशी को मंडी से पार्टी टिकट देगी, उसका साथ दिया जाएगा। सुक्खू सरकार के प्रति प्रदेशाध्यक्ष की नाराजगी भी अभी बरकरार है। उन्होंने कहा कि संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिका. रियों की अगर सरकार में समय से नियुक्तियां होतीं तो ठीक होता।

ऐसा नहीं होने के चलते अब चुनाव मैदान में सक्रिय कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। प्रतिभा बोलीं, मैंने अपने कार्यकाल में सिर्फ एमपी फंड ही बांटा है। इतने काम से चुनाव नहीं जीता जाता। पार्टी वर्कर भी निराश हो गए हैं। पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह बोलीं, मैं सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहना चाहती हूं। इस कारण ही चुनाव खुद नहीं लड़कर मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगी। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, उसे निभाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत दिलाना उनका कर्तव्य है। सभी कार्यकर्ताओं को भी पता है कि अब चुनाव का सामना करना है। सभी को. शिश करेंगे कि छोटी–मोटी नाराजगी दूर हो। प्रतिभा ने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए ही वह बार–बार कार्यकर्ताओं को महत्व देने की बात करती रहीं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना होगा। वह लगातार फील्ड में रही हैं। उन्हें नहीं लगता है कि वह ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगी। ऐसे में हाईकमान जिसे ठीक समझे, उसे चुनाव मैदान में उतारे।

मंडी से कौल, निगम और सोहन लाल के नाम पर चर्चा

प्रतिभा सिंह के लोकसभा चुनाव लडने़ से इन्कार करने के बाद अब मंडी से प्रत्याशी उतारने के लिए कांग्रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी, पूर्व विधायक सोहन लाल के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। कौल सिंह ने कहा कि हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होगा।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह ने मंडी से जीत दर्ज की है। पूरा संसदीय क्षेत्र घुमा हुआ है।

उनके जीतने की संभावना भी है। उन्हें ही चुनाव लडऩा चाहिए।

वहीं, नेगी निगम भंडारी ने कहा कि पार्टी के जो भी आदेश होंगे, उनका पालन करेंगे।

यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 28 मार्च से होंगी शुरू, फाइनल डेटशीट जारी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की पूर्व में जारी संभावित डेटशीट पर आईं आपत्तियों के बाद इसमें बदलाव कर फाइनल डेटशीट जारी कर दी है। 28 मार्च से यूजी डिग्री कोर्स बीए, बीएससी, बी कॉम और शास्त्री की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी जो 8 मई तक चलेंगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी डेटशीट को परीक्षार्थियों की सूचना के लिए विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसे छात्र देख और डाउलोड कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने परीक्षा के शेड्यूल के साथ ही कॉलेजों को तय की गई 22 मई तक हर हाल में छात्रों के इंटरनल असेसमेंट, सीसीए को अपलोड करने और इसकी वेरिफिकेशन करने को रिमाइंडर भेजा है।

इसमें चेताया गया है कि इंटरनल असेसमेंट, सीसीए अपलोड और वेरिफाई न होने पर छात्रों के परीक्षा रोलनंबर जनरेट नहीं होंगे।

रोलनंबर को लेकर पेश आने वाली परेशानी के लिए पूरी तरह से कॉलेज जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने कॉलेजों को समय से इंटरनल असेसमेंट अपलोड और वेरिफाई करने को कहा है।

हिमाचल सरकार ने 22 हजार परिवार बसाए भाजपा अपना योगदान बताए : सीएम सुक्खू

vkd lk f'keykA मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के 22 हजार से अधिक आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का कार्य किया है।

राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की सहायता के आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। इससे हजारों आपदा प्रभावितों की मदद हुई है। भाजपा नेताओं को जनता के सामने अपना योगदान बताना चाहिए। हिमाचल के भाजपा नेता केंद्रीय मदद मिलने में लगातार अड़ंगे लगाते रहे, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कोई भी विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर महंगे फाइव स्टार होटलों में ठहराया जा रहा है। हेलिकाप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सैर कराई जा रही है और उनकी सुरक्षा पर भी भाजपा भारी–भरकम पैसा खर्च रही है।

जब भी हिमाचल के हितों की बात आई। भाजपा नेताओं ने अपना हिमाचल विरोधी चेहरा दिखाया। प्रदेश की जनता अब भाजपा नेताओं से जवाब मांग रही है, लेकिन भाजपा से जवाब देते नहीं बन रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो भाजपा नेता चर्चा के दौरान तीन दिन तक बड़ी–बड़ी बातें करते रहे। जब वोटिंग की बारी आई तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। क्या ये लोग हिमाचल के हितैषी हो सकते हैं। वर्तमान राज्य सरकार कभी किसी राजनीतिक लाभ की मंशा से काम नहीं करती। हमारे कर्म में मानवता और सेवाभाव सर्वोपरि है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गोशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है। सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। वह एक साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। भाजपा सिर्फ राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सेवा भाव के साथ कार्य करने में विश्वास रखती है। भाजपा के आचरण को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख रखी है और आने वाले में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी।

प्रदेश की महिला शक्ति के सामने भाजपा की चाल, चरित्र बेनकाब–पठानिया

कांग्रेस सरकार के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा महिलाओं की आर्थिक समृद्धि की राह का सबसे बड़ा रोड़ा हैं। वह नहीं चाहते हैं कि पात्र महिलाओं के हाथ में सीधा पैसा आए। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को ठगने का काम किया और अब उन्हें सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार से मिलने वाले अधिकार को रोकने में जुट गए हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की महिला शक्ति के सामने भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र बेनकाब हो चुका है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि भाजपा महिलाओं के 1500 रुपये क्यों रोकना चाहती है। विपक्षी दल के नेताओं को प्रदेश की महिलाओं का उत्थान क्यों पसंद नहीं आ रहा?

प्रदेश भाजपा को जनता को बताना चाहिए कि बीते पांच साल हिमाचल की सत्ता में रहते महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए। कुछ समय पहले तक वह रोजाना महिलाओं को 1500–1500 रुपये देने की मांग करते आ रहे थे, अब सरकार ने जब पूरी योजना अधिसूचित कर दी है और अगले वित्त वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान कर दिया है तो अचानक जयराम ठाकुर को क्यों इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना चुभने लगी है।

पठानिया ने कहा भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। विपक्षी दल प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होते नहीं देखना चाहता। भाजपा महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक ही समझती है। सुक्खू सरकार लाखों पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल से 1500 रुपये मासिक देने जा रही है तो भाजपा व नेता प्रतिपक्ष उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं।

जनता जान चुकी है कि भाजपा की नीयत में खोट है। आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में महिलाएं भाजपा को करारा सबक सिखाएंगी।

शक्ति के बहाने मातृशक्ति के स्वाभिमान को कुचलना चाहती है कांग्रेस : अनुराग ठाकुर

vkd lk ekeh'kkykA केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की ओर से शक्ति पर दिए गए बयान के पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा की सनातन की भक्ति शक्ति में है और देश की प्रत्येक माता और बहन हमारे लिए शक्ति स्वरूप है।

कांग्रेस पार्टी शक्ति के बहाने मातृशक्ति के स्वाभिमान को कुचलना चाहती है और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अपनी जीत को 95 फीसदी हिंदुओं की हार के रूप में दिखाया था।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम हिंदू बुराइयों से लडने़ के लिए शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शक्ति को ही खत्म करना चाहते हैं। श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान तमिलनाडु देश का एक राज्य ऐसा भी था जिसने वहां के मंदिरों में इसके सीधे प्रसारण पर रोक लगाई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनसे अपना घर नहीं संभल पा रहा है, वह हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई महीनों से लगातार उनके विधायक आरोप लगा रहे थे कि उनका मुख्यमंत्री सुनता नहीं है। उनके खुद के काम अपनी सरकार में नहीं हो रहे थे। जो जनता से वादे किए गए थे वह पूरे नहीं हुए। सरकार बनने के पहले दिन से उनका अहंकार झलक रहा था।

सूबे मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां 95 हिंदू रहते हैं वहां हमने हिंदुओं को हराकर सरकार बनाई है। आज 15 महीने बीत जाने के बाद भी नारी शक्ति को वादे के मुताबिक 1,500 रुपये प्रति महीने नहीं मिले। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, नहीं दिया। 2 रुपये प्रति किलो गोबर और 100 प्रति किलो दूध खरीदने का वादा किया था, नहीं पूरा किया। स्टार्टअप फंड के लिए 600 करोड़ रुपये नहीं दिए। फल किसानों को सही और मुंहमांगे दाम देने का वादा किया था, नहीं दिया। आलम ये था कि किसानों को अपने फल नदी में बहाने पड़े।

पांच बार प्रथम श्रेणी, एक बार सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड हिमाचलियों के नाम

vkd l k f'keykA लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के प्रति हिमाचलियों का उत्साह कभी कम नहीं हुआ है। पांच बार प्रथम श्रेणी (60 फीसदी से अधिक मतदान) और एक बार देश में सर्वाधिक मतदान 72.42 फसदी का रिकॉर्ड हिमाचलियों के नाम है। केंद्र में सरकार चुनने को हर चुनाव में प्रदेश के मतदाता बढ़चढ़ कर भाग लेते आ रहे हैं। वर्ष 1977 में 59 फीसदी से वर्ष 2019 तक मतदान प्रतिशतता 72 फीसदी तक पहुंच गई। ये आंकड़े हिमाचलियों के जोश और जज्बे के गवाह हैं।

मतदाताओं के जज्बे को देखते हुए ही इस बार चुनाव आयोग ने हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्रों में मतदान का लक्ष्य 75 फीसदी पार करने का रखा है। आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल में हुए लोकसभा चुनावों की मतदान प्रतिशतता देश की प्रतिशतता के बराबर या अधिक ही रही है। पिछले 12 चुनावों में पांच बार 1984–85, 1989, 1998, 2014 और 2019 के दौरान हिमाचल के मतदाता प्रथम (60 फीसदी से अधिक मतदान) श्रेणी में पास हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहाड़ी राज्य के मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान कर इतिहास रचा था। चुनाव में देवभूमि में रिकॉर्ड 72.42 फीसदी मतदान हुआ था। वर्ष 1998 में 65.32 प्रतिशत था।

महिलाओं की बढ़ती गई मतदान में भागीदारी

वर्ष	पोलिंग स्टेशन	कुल मतदाता	मतदान हुआ	मतदान प्रतिशत
1977	3361	19,61,050	11,67,927	59.56
1980	3742	21,75,326	12,77,049	58.70
1984–85	4129	23,14,024	14,22,000	61.45
1989	4678	29,83,759	19,07,671	63.94
1991	4681	30,76,182	17,65,627	57.40
1996	5721	35,36,517	20,36,415	57.58
1998	6230	36,28,864	20,06,774	65.32
1999	6230	37,86,479	21,49,816	56.78
2004	6232	41,81,995	24,97,149	59.71
2009	7253	46,06,674	26,91,573	58.43
2014	7382	48,10,071	31,00,199	64.45
2019	7730	53,30,154	38,59,940	72.42

हिमाचल में वर्ष 1977 के चुनाव में महिलाओं की मतदान प्रतिशतता 44.8 फीसदी थी। 1980 में 44.5 फीसदी, 1984–85 में 47.1 फीसदी, 1991 में 46.1, 1996 में 48.4, 1998 में 66.3, 1999 में 54.3 और 2004 में 59.03 फीसदी मतदान प्रतिशतता रही है। वर्ष 2009 के चुनाव में 59.5 और 2014 में 65.4 फीसदी ने मतदान किया था। 2019 के चुनाव में महिलाओं ने रिकॉर्ड 74.31 फीसदी मतदान किया था। पुरुषों की मतदान प्रतिशतता 70.61 रही थी।

दुर्गम इलाके लेते हैं मतदाताओं की परीक्षा

हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति जैसे जिलों में कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, जो मतदाताओं भी परीक्षा लेते हैं। दुर्गम क्षेत्रों के मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कई तरह की मुश्किलें पेश आती हैं। वहीं, पोलिंग पार्टियों के लिए भी पो. लिंग बूथों तक पहुंचना आसान नहीं है। कहीं नाव तो कहीं हेलिकाप्टर से ईवीएम मतदान केंद्रों तक पहुंचानी पड़ती है। इस सब के बावजूद वोट डालने के लिए मतदाताओं में अलग ही जोश नजर आता है।

1996 में सबसे ज्यादा, 1977 में सबसे कम प्रत्याशी उतरे थे चुनाव मैदान में प्रदेश में 1977 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक प्रत्याशी 1996 के चुनाव में उतरे थे। वर्ष 1996 के चुनाव में प्रदेश के चार संसदीय क्षेत्रों से 54 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 1977 के चुनाव में सबसे कम 14 प्रत्याशी ही मैदान में उतरे थे। 1980 में 29, 1984–85 में 31, 1989 में 33, 1991 में 45, 1998 में 22, 1999 में भी 22, 2004 में 23, 2009 में 31, 2014 में 38 और वर्ष 2019 के चुनाव में 45 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था।

अंतरिम रोक जारी रहेगी हाटियों को जनजातीय दर्जे पर, 27 मई को होगी सुनवाई

vkd l k f'keykA हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटियों को जनजातीय दर्जा देने से जुड़े कानून के अमल पर अंतिम रोक जारी रखी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब दायर न करने पर सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे का मामला एक बार फिर अटक गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रविचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने की।

इसके साथ ही कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से 1 जनवरी 2024 को जारी उस अधिसूचना पर भी रोक रहेगी, जिसमें उपायुक्त को जनजातीय प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश हुए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अदालत में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। इस मामले को सिरमौर जिले की गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार सरंक्षण समिति, पिछड़ा वर्ग, गुर्जर समाज कल्याण परिषद और अन्य ने ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी समुदाय के लोग 1967 से उत्तराखंड के जौनसार बाबर को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद से संघर्ष कर रहे हैं। कई वर्षों तक लगातार संघर्ष के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय की मांग को 14 सितंबर 2022 को अपनी मंजूरी दी थी।

उसके बाद केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को इस विधेयक को लोकसभा में पारित करवाया। उसके बाद यह विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने 9 दिनों के अंदर ही विधेयक पर मुहर लगा दी। हाटी समुदाय में करीब 2 लाख लोग 4 विधानसभा क्षेत्र शिलाई, रेणुका, पच्छाद और पांवटा साहिब में रहते हैं। जिला सिरमौर की कुल 269 पचायतों में से ट्रांसगिरी में 154 पंचायतें आती हैं। इन 154 पंचायतों की 14 जातियों तथा उप–जातियों को एसटी संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है।

सुखविंद्र सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार में सबसे कम खर्च कर विधायक बने थे

vkd l k f'keykA मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सबसे कम खर्च कर विधायक बने हैं। एडीआर(एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की ओर से चुनाव में कम और ज्यादा खर्च करने वाले विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। सीएम सुक्खू के बाद कम खर्च करने के मामले में चंबा सदर के विधायक नीरज नैय्यर दूसरे स्थान पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर अधिक खर्च करने वाले विधायकों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। जानकारी के अनुसार सुक्खू ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 11 लाख रुपये की राशि खर्च की है। चंबा सदर के विधायक नीरज नैय्यर ने बारह लाख चुनाव प्रचार–प्रसार में खर्च किए हैं। दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2022 के चुनाव में करीब 35 लाख रुपये की राशि चुनाव प्रचार–प्रसार के दौरान खर्च की है। वह अधिक खर्च करने वाले विधायकों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं। अधिक खर्च करने के टॉप में भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान 36 लाख की राशि खर्च की है। दूसरे स्थान पर भाजपा विधायक डॉ. विपिन सिंह परमार हैं। इन्होंने चुनाव में 36 लाख की राशि व्यय की है। अधिक व्यय करने वाले टॉप टेन विधायकों में आठ विधायक भाजपा के हैं। महज दो विधायक ही कांग्रेस के हैं। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने यह आंकड़े जारी किए हैं।

अंतरराज्यीय पशु चोर गिरोह का किया पुलिस ने भंडाफोड़, दो आरोपी गिरतार

vkd l k ukgu ¼fl jekSj½A हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय पशु चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए हरियाणा निवासी दो आरोपियों को गिरतार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टा, 5 रौंद व टेंपो भी किए बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 10 सालों से देसी कट्टा रखे हुए थे। आरोपियों की आयु 30 साल से भी कम है। पुलिस के अनुसार आरो. पियों ने यहां पहले भी तीन बार कालाअंब पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात को पशु चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसे लेकर मामले भी दर्ज किए गए हैं।

एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने पत्रकारवार्ता में बताया कि पुलिस थाना कालाअंब में 5 मार्च को सुरेंद्र पुत्र भूलर सिंह निवासी गांव कटोला डहर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 4 मार्च की रात को इसकी पशुशाला से भैंसें चोरी करने की को. शिश की गई थी। उन्होंने जैसे ही आरोपियों को देखा और वे टेंपो में मौके से फरार हो गए। आरोपियों फरार होते फायर किया।

एसपी ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने तुरंत डीएसपी मुख्यालय रमाकांत ठाकुर के पर्यवेक्षण में पुलिस थाना प्रभारी मोहर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने अलग–अलग दिशाओं में आठ मुख्य मार्गों से होते हुए 74 लिंक मार्गों से 68 सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण करते हुए लगभग 98 किलोमीटर का रास्ता तय किया।

10 दिनों के भीतर मुख्य आरोपियों व उनके गांवों की पहचान की गई। पुलिस ने हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा पर हथनीकुंड के नजदीक जिला यमुनानगर हरियाणा से आरोपी असलम उर्फ(29) इसलाम निवासी गांव खैरी बास व सह आरोपी सद्दाम(24) निवासी गांव मुजाहिदपुर, फतेहपुर जिला सहारनपुर को गिरतार किया गया। वारदात में इस्तेमाल टेंपो, मकान के आंगन से फायर आर्म व पांच रौंद बरामद किए हैं । एसपी ने बताया कि आरोपी सद्दाम के विरूद्ध चोरी, गोवध, गैंगस्टर अधिनियम के तहत हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्य में मामले पंजी.त हैं।

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ व साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि आरोपी सद्दाम पशुओं की मो. हरी (पशु बाधने बाली रस्सी) को बेचने का काम करता था तथा मोहरी बेचने के बहाने हिमाचल में लोगों के घर आकर पशुओं की रेकी करता था। रेकी करने के बाद यह पशु तस्कर बिना नंबर का टेंपो को तिरपाल से ढककर सोमवार को हिमाचल राज्य में प्रवेश करते थे तथा पशुओं को रात में चुराकर दूसरे दिन सहारनपुर पशु मंडी में ले जाकर बेच देते थे।

रिकॉर्ड बनाया छह शेफ ने 451 किस्म के सिड्डू तैयार कर

vkd l k f'keykA हिमाचल टूरिज्म हिम आंचल शेफ एसोसिएशन ने मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में हिमाचल कल्नरी चौलेंज और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। पर्यटन विभाग के प्रबंध निद. ेशक राजीव कुमार ने बतौर मुख्यातिथि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाहरी राज्यों गुजरात, अहमदाबाद, पंजाब से आए शेफ ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। हिमाचली व्यंजनो को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन ने 451 किस्म के सिड्डू बनाए हैं। हिमाचल में पहली बार इतनी किस्म के सिड्डू बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मंगलवार को चल रही प्रतियोगिता में एसोसिएशन के छह शेफ ने ये सिड्डू तैयार कर प्रदर्शित किए। सुबह चार बजे से छह शेफ ने सिड्डू बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। दोपहर एक बजे इन्हें प्रदर्शित किया गया। छह शेफ ने 451 किस्म के सिड्डू तैयार किए। उन्होंने हर किस्म के तीन सिड्डू बनाए हैं। यहां कुल 1300 सिड्डू बनाए गए। अब इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान शिमला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन नेगी, एडीएम ज्योति राणा और पर्यटन विभाग निद. ेशक राजीव कुमार ने सिड्डू का स्वाद चखा। हिम आंचल शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद लाल ने बताया कि हिमाचल व्यंजन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में पहली बार 451 किस्म के सिड्डू तैयार कर रिकॉर्ड बनाया गया है। एक महीने इस रिकॉर्ड की तैयारी चली हुई थी। एसोसिएशन के छह शेफ ने इन्हें तैयार किया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने के लिए भेजा जाएगा।

ehBs] uedhu r:;kj fd, 451 fdLe d: fl i

एसोसिएशन के छह शेफ ने मीठे, नमकीन 451 किस्म के सिड्डू को तैयार किए हैं। इन्हें ड्राई फ्रूट्स, सब्जियों, मोटा अनाज, दालें, मिठाइयों, चॉकलेट, गुच्छी, देसी शक्कर, ड्राइनट्स से बनाया गया है। इसके साथ ही कई सिड्डू बाहरी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र के व्यंजन कचौरी, थिपेला से भी तैयार किए गए हैं।

cPpk u: Hkh fn[kkbl ikd dyk

इस दौरान चिल्ड्रन शेफ, स्टूडेंट शेफ और प्रोफेशनल शेफ वर्गों में स्पर्धा हुई, जिसमें प्रदेश और बाहरी राज्यों से 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चिल्ड्रन शेफ स्पर्धा में 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। सात बच्चों ने पाक कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान एडवर्ट स्कूल के मनन ने गाजर और दूध से कैरेड कप केक डिश बनाई, रिशान वासुदेवा ने चार्ट और चीज, हृदय ने पनीर टिक्का, अभ्युदय चौहान ने चॉकलेट, आरव रतन ने मूली का खट्टा और मीठे चावल, ताराहॉल स्कूल से आहाना ने चिकन टिक्का डिश बनाई।

साथ ही गुजरात से लोक ने इस स्पर्धा में भाग लिया। लोक ने यूनिक केक ढोकला बनाया। इसे चावल, उड़द, चने, मूंग की दाल से तैयार किया गया है। हिम आंचल शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छिपे हुए हिमाचली व्यंजनों, फसलों, संस्.ति की खोज में घरेलू रसोइयों गृहिणियों, पेश. ेवर रसोइयों को एक साथ लाना, राज्य की महिलाओं के लिए अपने मनोबल को बढ़ावा देने और एक उद्यमी, आत्मनिर्भरता के रूम में सामने आने के लिए एक मंच स्थापित करना है।

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की तस्वीर लगवाई इंद्रजीत की जगह, बिशंबर वाल्मीकि ने संभाला कार्यभार

pMhx<A हरियाणा में पिछले एक सप्ताह में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब नेताओं को भूमिका बदल गई है। जजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नए मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को कार्यालय अलॉट कर दिए गए। मनोहर सरकार–2 में कैबिनेट मंत्री रहे पांच मंत्रियों के पास पुराने कार्यालय ही रहेंगे, जबकि अन्य मंत्रियों को अलग–अलग तल पर ऑफिस दिए हैं। खास बात ये है कि बवानीखेड़ा के विधायक से राज्यमंत्री बने बिशंबर वाल्मीकि ने बुधवार को आठवें तल पर मिले कार्यालय कमरा नंबर 43–सी में पहुंच कार्यभार संभाला। साथ ही यहां पर लगी राव इंद्रजीत की तस्वीर हटवाकर बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की तस्वीर लगवाई है। आठवें तल पर स्थित यह कार्यालय ओपी यादव के पास था और वह राव के पक्के समर्थक हैं। जबकि बिशंबर वाल्मीकि अनुसूचित जाति से आते हैं और बाबा साहेब का अपना आदर्श मानते हैं।

आंवटन के मुताबिक ज्यादातर मंत्रियों को आठवीं मंजिल पर ही कार्यालय आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल को पांचवीं मंजिल पर पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कार्यालय नंबर–40 दिया गया है, जबकि सुभाष सुधा नौवीं मंजिल पर पूर्व मंत्री संदीप सिंह के कार्यालय कमरा नंबर–30 से अपना विभाग चलाएंगे। वहीं, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के ऑफिस में राज्यमंत्री सीमा त्रिखा बैठेंगी, उन्हें 32 नंबर कमरा अलॉट किया गया है। इसके साथ ही छठी मंजिल पर पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का दतर कमरा नंबर 40–बी राज्यमंत्री असीम गोयल को आवंटित किया गया है। आठवीं मंजिल पर पूर्व श्रममंत्री अनूप धानक का ऑफिस कमरा नंबर–47 अब राज्यमंत्री महिपाल ढांडा संभालेंगे। इसी प्रकार, राज्यमंत्री संजय सिंह को 43–ए कमरा नंबर अलॉट किया गया है। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के दतर कमरा नंबर–31 में राज्यमंत्री अभय यादव बैठेंगे।

पांच मंत्रियों को पुराने दतर अलॉट

मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ शपथ लेने वाले पांच कैबिनेट मंत्रियों के पास पुराने दतर ही रहेंगे। कंवरपाल गुर्जर का दतर आठवीं मंजिल पर कमरा नंबर–34 ही रहेगा। जबकि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी आठवीं मंजिल पर पुराने कार्यालय कमरा नंबर–49 में ही बैठेंगे। रणजीत चौटाला का दतर कमरा नंबर–39 में ही चलेगा। इसके साथ ही बनवारी लाल भी अपना दतर कमरा नंबर–24 से ही चलगाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल के पास छठी मंजिल पर पुराना दतर ही रहेगा। वे कमरा नंबर–42 से ही कामकाज करेंगे।

बधाई देने पहुंच रहे समर्थक

कार्यालय अलॉट होते ही राज्यमंत्री संजय सिंह और बिशंबर वाल्मीकि अपने कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में उनके समर्थकों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। अहम पहलू यह भी है कि दोनों मंत्रियों ने कामक. ाज भी शुरू कर दिया। समर्थकों से संबंधित काम को लेकर अधिकारियों को फोन भी किए। हालांकि, अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं मिल पाए हैं।

पांच महीने में हुई आग लगने की तीसरी घटना, पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग

pMhx<A चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस ट्रॉमा सेंटर के फॉल सीलिंग में मंगलवार शाम 4:10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वार्ड के पास एटीसी की लिट नंबर 5 की गलियारे में फॉल सीलिंग से धुआं निकलता देख अफरा–तफरी मच गई। पीजीआई प्रशासन ने दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तत्काल मरीजों को अन्य वार्डों में शिट कर दिया। हालांकि, पीजीआई प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। इसमें किसी भी तरह के जानमाल की क्षति नहीं हुई है।

वार्ड में 60 मरीज थे भर्ती

ट्रॉमा सेंटर के पांचवी मंजिल पर वार्ड में उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी, ईएनटी और ऑर्थोपेडिक्स विभाग के लगभग 60 मरीज भर्ती थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग बुझाने वाले उपकरणों के माध्यम से लगभग 5 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया लेकिन अगले आधे घंटे तक ग्राउंड लोर तक धुआं उठता रहा। वहीं, फॉल सीलिंग के जंक्शन बॉक्स में लगी आग के कारण लगभग छह फीट का हिस्सा जल गया।

तत्काल बहाल हुई बिजली

पीजीआई प्रशासन के अनुसार 5वीं मंजिल पर ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग ऑफिसर और सुरक्षा गार्ड्स ने फॉल सीलिंग से निकलता धुआं देखकर तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद अग्निशमन और सुरक्षा गार्ड्स की टीम ने 5 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। वहीं, इलाज प्रभावित होने के डर से अस्पताल के इंजीनियरिंग विंग को तत्काल घटनास्थल पर बुला लिया गया, जिसने शॉर्ट सर्किट के बाद जले हुए पैनल को हटाकर बिजली बहाल कर दी।

कारणों की जांच शुरू

पीजीआई प्रशासन घटना के कारणों की जांच में जुट गया है। वहीं, इंजी. नियरिंग विभाग ने तार के टुकड़े को जांच के लिए एकत्र कर लिया। बता दें की एडवांस ट्रॉमा सेंटर 2011 में शुरू हुआ था। जहां चंडीगढ़ के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आसपास के अन्य जिलों के ट्रॉमा के केस रेफर किए जाते हैं।

पिछली दो आग लगने की घटनाओं के बाद गठित जांच कमेटी ने बचाव के लिए दिए थे ये सुझाव

– अग्निशमन वाहनों के लिए पहुंच मार्ग/निर्दिष्ट अग्निशमन क्षेत्र खुले और खाली रखे जाएं

– नई ओपीडी में भूतल पर अग्नि निकास मार्गों को कांच/लकड़ी के दरवाजों से बदला जाए

– भारी वाहनों के आवागमन के लिए नेहरू अस्पताल के सामने क्रॉसिंग रोड बनाई जाए

– अस्पताल के ब्लॉकों में अग्नि निकास दरवाजे बाहर की ओर खुलें।

चौंकाने वाला होता है फैसला, यहां हर चुनाव में बदलता मतदाता का मिजाज

tkyèkjA पंजाब के मतदाता हर लोकसभा चुनाव में अपने मिजाज बदलते रहते हैं। हर चुनाव में यहां की राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है। सूबे में जो पार्टी सत्ता में होती है, उसको कुछ फायदा जरूर मिलता है, लेकिन पंजाब के मतदाता हर चुनाव में चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा की आठ सीटों पर जीत हासिल कर पंजाब में नरेंद्र मोदी की लहर को

इससे सभी राजनीतिक विश्लेषक हैरान रह गए थे। हालांकि, वर्ष 2022 तक आते–आते तस्वीर बदलने लगी, जो कांग्रेस सूबे में नंबर वन थी, आम आदमी पार्टी उससे काफी आगे निकल गई। आप ने पंजाब में 92 सीटों पर परचम लहराकर कांग्रेस का किला ध्वस्त किया। साथ में शिरोमणि अकाली दल को भी तीन सीटों पर सिमटने पर मजबूर कर दिया। भाजपा दो सीटों पर ही अटक गई।

2014 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार थी और आप को लोकसभा में चार सीटें मिली थीं। यह काफी चौंकाने वाला नतीजा था। पटियाला से धर्मवीर गांधी, संगरूर से भगवंत मान, फतेहगढ़ साहिब से हरिंदर सिंह खालसा व फरीदकोट से प्रो. साधू सिंह चुनाव जीते थे।

आप को 24.40 फीसदी मत हासिल हुए थे। कांग्रेस को 33.10 फीसदी वोट, भाजपा को 8.70 फीसदी व अकाली दल को 26.30 फीसदी मत हासिल हुए थे। कांग्रेस 13 में से तीन सीटें ही जीत पाई थी, जबकि चार पर आप और बाकी छह पर भाजपा–शिअद गठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। पंजाब में तब शिरोमणि अकाली दल व भाजपा की सरकार थी।

2019 में तस्वीर बिलकुल बदल गई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार 2017 में सत्तासीन हो चुकी थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 33.10 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी तक पहुंच गया। कांग्रेस ने जहां 2014 में तीन सीट जीती थीं, वहीं 2019 में आठ सीटों पर परचम लहराया।

वहीं, आम आदमी पार्टी के चार सांसद थे, लेकिन भगवंत मान अकेले रह गए और वोट प्रतिशत गिरकर 7.38 फीसदी आ गया। 2014 में आप का वोट प्रतिशत 24.4 फीसदी था, जो 7. 38 फीसदी आ गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल का वोट प्रतिशत बढ़कर 27.45 फीसदी हो गया, जोकि 2014 में 26.3 फीसदी था। अकाली दल व भाजपा के दो–दो सांसद रह गए। भाजपा ने होशियारपुर व गुरदासपुर सीट जीतकर 9.63 फीसदी वोट हासिल किए।

अब पंजाब की राजनीतिक तस्वीर फिर बदल चुकी है। 2022 में आप ने पंजाब में प्रचंड जीत हासिल की है। आप ने 92 सीटें विधानसभा में जीती हैं और 2019 में जो वोट 7.38 फीसदी था। वह सीधा जंप कर 42.3 फीसदी तक जा पहुंच गया। कांग्रेस जो 40 फीसदी थी, वह 23.1 फीसदी पर आकर गिर गई। शिरोमणि अकाली दल जो 2019 में 27.45 पर था, वह 18.5 प्रतिशत पर आ गया।

उपचुनाव में भी चौंकाया

भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद संगरूर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में भी पंजाब के मतदाताआ. ें ने चौंकाने वाला काम किया। यहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह चुनाव हार गए। यहां से शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के सिमरनजीत सिंह मान को चुनाव में जीत मिली। उन्होंने गुरमेल सिंह को 5822 मतों से हराया। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के दौरान कम मतदान हुआ था। यहां केवल 45 फीसदी वोट पड़े थे, जो 2019 के चुनावों की तुलना में 27.1 प्रतिशत कम था।

संगरूर लोकसभा से चुनाव जीतने वाले सिमरनजीत सिंह मान आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं।

सिमरनजीत मान 1989 में तरनतारन से और 1999 में संगरूर सीट से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद जालंधर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, क्योंकि चौधरी संतोख सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी कर्मजीत कौर चौधरी मैदान में थीं।

माना जा रहा था कि उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सहानुभूति वोट मिलेगा, लनेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप के उम्मीदवार सुशील रिंकू ने कांग्रेस की उम्मीदवार कर्मजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस इससे पहले चार बार से यह सीट जीत रही थी। चौथे नंबर पर शिअद अमृतसर के गुरजंट सिंह को 20354 वोट मिले थे।

यह लोकतंत्र की खूबसूरती है

डीएवी यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चां. सलर प्रो. जसबीर कौर रिशी का कहना है कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोट का स्विंग होना हमेशा बेहतरी के लिए गिना जाता है। इसका मतलब है कि पंजाब के लोग एक पार्टी पर विश्वास नहीं करते। अपना वोट मौके व उम्मीदवार व पार्टी को देखकर करते हैं।

पिछले तीन चुनाव की स्थिति

2019 केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी

कुल मतदान– 65.94 प्रतिशत (कांग्रेस 40.12 प्रतिशत वोट– 8 सीटें, भाजपा 9.63 प्रतिशत वोट 2 सीटें, आप 7.38 प्रतिशत 1 सीट, शिअद 27.76 प्रतिशत वोट 2 सीटें)

2014 केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी

–कुल मतदान– 70.63 प्रतिशत (शिअद 26.30 प्रतिशत 4 वोट 4 सीटें, आप 24.4 प्रतिशत वोट 4 सीटें, कांग्रेस 33.10 प्रतिशत वोट 3 सीटें, भाजपा 8.70 प्रतिशत वोट 3 सीटें)

2009 कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी

–कुल मतदान– 69.78 प्रतिशत (कांग्रेस 34.17 प्रतिशत वोट 2 सीटें, शिअद 34.28 प्रतिशत वोट 8 सीटें, भाजपा 10.48 प्रतिशत वोट 3 सीटें)

यहां जो भी सीएम आया चली गई कुर्सी मनोहर भी नहीं तोड़ पाए मधुबन का मिथक

pMhx<A करनाल जिले में स्थित मधुबन पुलिस अकादमी का मिथक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नहीं तोड़ पाए। धारणा है कि जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री मधुबन आया, कुछ ही महीनों बाद उसकी कुर्सी चली गई। मधुबन जाने के बाद प्रदेश के मुखिया की कुर्सी से हटने वालों में अब मनोहर लाल का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले चौधरी बंसीलाल, मास्टर हुकुम सिंह और ओमप्रकाश चौटाला मधुबन जाने के बाद सीएम की कुर्सी गंवा चुके हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मधुबन का मिथक तोड़ने की कोशिश की थी। वह 14 जनवरी 2018 को पहली बार सीएम रहते हुए मधुबन पहुंचे थे। सीएम के लिए अशुभ मानी जा रही पुलिस अकादमी के मिथक को तोड़ते हुए मनोहर लाल ने तब दीक्षांत परेड में हिस्सा लिया था। हालांकि, 2019 में वह फिर से सीएम बन गए थे। पिछले साल 14 फरवरी 2023 को भी मनोहर लाल ने यहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर सम्मान मिलने पर आयोजित निशान अलंकरण परेड में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। इसके ठीक एक साल बाद मनो. हर लाल के पास से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। अब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री और मनोहर लाल करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं।

कन्नी काटते रहे कई सीएम

मधुबन अकादमी की स्थापना सन 1976 में हुई थी। इसके बाद केंद्र के मंत्रियों और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित अन्य कई नेता जवानों का हौसला बढ़ाने अकादमी पहुंचे और दीक्षांत परेड में हिस्सा लिया। लेकिन मधुबन अकादमी में हरियाणा के कुछ मुख्यमंत्रियों के आने के बाद उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद मुख्यमंत्रियों ने अकादमी में आने से कन्नी काटना शुरू कर दिया। इनमें चौधरी भजन लाल, बनारसी दास गुप्ता समेत अन्य नाम शामिल हैं।

इनकी गई कुर्सी वर्ष 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल अकादमी पहुंचे थे और 1987 में उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद दो मार्च 1991 में जनता दल के मुख्यमंत्री हुकम सिंह अकादमी में पहुंचे और 21 मार्च को उनकी कुर्सी चली गई। उनके बाद ओमप्रकाश चौटाला सीएम बने। साल 2001 में चौटाला यहां आए थे और 2005 में उनकी सरकार चली गई। इसके बाद वह दोबारा सीएम नहीं बन पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल सीएम रहे, लेकिन एक बार भी मधुबन कांप्लेक्स नहीं आए।

10वीं के बाद की टॉप सरकारी नौकरियां, मिलेगी बढ़ियां सैलरी

ऐसे बहुत से लोग हैं जो दसवीं करने के बाद नौकरी करना चाहते हैं ऐसे में अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसे अच्छी क्या बात हो सकती है। परंतु इन सभी सरकारी नौकरियों के बारे में आपको पता हो यह जरूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो हमारा यह आर्टिकल आप ही के लिए है। इसमें हमनें कई सारी नौकरियों के बारे में जानकारी दी है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी एक को चुन सकते हैं। 10वीं कक्षा के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियां........

राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा

अगर आपकी रूचि पुलिस फॉर्स ज्वाइन करने की है, तो आप विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दे सकते हैं। कई राज्य पुलिस विभाग 10वीं कक्षा के बाद कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। पुलिस कांस्टेबल सबसे निचले दर्जे का पुलिस अधिक. ारी होता है। वह सम्मन और वारंट देता है और अपराधियों को गिरतार करता है।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल भारत का सीमा रक्षक संगठन है और भारत के पांच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सज में से एक है। क्यस्स्न विभिन्न ट्रेडों के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती करता है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 10 है। इसी तरह आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इंडियन कोस्ट गार्ड

इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की एक मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है, जो अपने आस पास के क्षेत्र में मैरीटाइम लॉ को एनफोर्स करती है। इसके बाकि कामों में मरीन एनवायरनमेंट को बचाना, सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाना आदि शामिल हैं। आप इंडियन कोस्ट गार्ड में 10वीं कक्षा के बाद सेलर (सामान्य ड्यूटी) के रूप में ज्वाइन हो सकते हैं।

भारतीय सेना सैनिक भर्ती

भारतीय सेना में नौकरी पाना अपने में बहुत गर्व की बात है। अगर आपका भी सपना है सेना में भर्ती होने का, लेकिन आपने सिर्फ 10वीं तक ही पढाई की है तो घबराइए नहीं। सेना विभिन्न श्रेणियों जैसे सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक तकनीकी, सैनिक क्लर्क/स्टोरकीपर तकनीकी आदि के लिए भर्ती निकालती रहती है। इन सभी के लिए सिर्फ कक्षा 10 पास करना जरुरी होता है।

भारतीय नौसेना

भारतीय सेना की तरह ही भारतीय नौसेना भी 10वीं पास छात्रों के लिए कुछ पदों पर भर्ती निकालती है। आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन मेट पद के लिए 10वीं कक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकालती है।

भारतीय वायु सेना

भारतीय सेना और नौसेना की तरह ही भारतीय वायु सेना में भी 10वीं पास छात्रों के लिए वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वायु सेना विभिन्न ग्रुप सी सिवि. लियन पदों के लिए भर्ती आयोजित करती है, जिसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ , लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक आदि की भर्ती शामिल है।

रेलवे भर्ती बोर्ड

जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो रेलवे कैसे पीछे रह सकता है। रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्ती निकलती ही रहती हैं।

10वीं कक्षा पास किए हुए छात्रों के लिए विभिन्न तकनीकी विभागों में ट्रैक मेंटेनर और हेल्पर/असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।

बच्चों को मातृभाषा में ही मिलेगी मिडल तक की शिक्षा,शिक्षा मंत्रालय की बड़ी पहल

शिक्षा को नया रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। नई शिक्षा नीति में आठवीं तक मातृभाषा में शिक्षा देने की पहल की गई है। जिन 52 भारतीय भाषाओ. ॅं में किताबें लॉन्च की गई हैं, उनमें करीब 17 आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए 52 प्राइमर्स लॉन्च किए गए है। गैर–अनुसूचित भाषाएं भारत में बोली जाती हैं।

बच्चों को अपनी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा मिले, इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय गैर–अनुसूचित भाषाओं में 52 लघु पाठ्यपुस्तकें जारी की। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में शुरू की गई यह पहल स्कूली शिक्षा के लिए गेम चेंजर है। भारतीय गैर–अनुसूचित भाषाओं में लघु पाठ्यपुस्तकें बच्चों के लिए एक परिवर्तनकारी कदम बनने जा रही हैं। बच्चों की शुरुआती शिक्षा उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में मिलेगी।

शिक्षा को नया रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम

शिक्षा को नया रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। नई शिक्षा नीति में आठवीं तक मातृभाषा में शिक्षा देने की पहल की गई है। जिन 52 भारतीय भाषाओ. ॅं में किताबें लॉन्च की गई हैं, उनमें करीब 17 आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए 52 प्राइमर्स लॉन्च किए गए है। गैर–अनुसूचित भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। छात्रों के लिए लघु पाठ्यपुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के सहयोग से तैयार की गई हैं।

भारतीय भाषाओं में सीखने को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह पहल भारतीय भाषाओं में सीखने को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को साकार करेगी और स्कूली शिक्षा में एक बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम साबित होगी। सभी स्तरों पर शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र का राज्य इकाइयों और 200 टीवी डीटीएच चौनलों के साथ एकीकरण का भी निर्णय लिया गया है।

आगे की तैयारियों के लिए काम शुरू

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आठवीं तक सभी को मातृभाषा में शिक्षा देने का कदम उठाया गया है, जिस पर काम शुरू हो गया है। ये सभी भाषाएं वैसे तो बहुत सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं, बावजूद इसके मंत्रालय ने इन भाषाओं में भी स्कूली स्तर पर शिक्षा देने की तैयारी की है। इसे लेकर 52 भाषाओं में तैयार की गई शुरुआती किताबों को लॉन्च किया गया है, जो जल्द ही इन क्षेत्रों में पढने के लिए दी जाएंगी।

नवोदय विद्यालय में कैसे मिलता है एडमिशन,जानिए योग्यता सहित अन्य डिटेल्स

नवोदय विद्यालय देश के बेहतरीन स्कूलों में शामिल है। यहाँ हर साल 6, 9 और 11वीं कक्षाओं में एडमिशन के लिए भारी संख्या में छात्र–छात्राएं फॉर्म भरते हैं। अगर आप भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो, यह आर्टिकल पढ़िए। हमनें इसमें एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी दी है। देखिये इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एक सिलेक्शन टेस्ट पास करना होता है। यह टेस्ट सीबीएसई द्वारा डिजाइन और कंडक्ट किया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह नॉन–वर्बल और क्लास न्यूट्रल टेस्ट होता है। दूर–दराज के क्षेत्रों के बच्चों को बिना किसी कठिनाई के एडमिशन फॉर्म फ्री में दिए जाते हैं। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों, पैम्फलेटों, विद्यालय की वेबसाइटों और जिले के स्थानीय स्कूलों में नवोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के दौरों के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

केंद्रीय विद्यालय की फीस कितनी है? आज भी लगते हैं सिर्फ 25 रुपये

केंद्रीय विद्यालय स्कूल फीस कितनी है? केवीएस एडमिशन की फीस के तौर पर सिर्फ 25 रुपये लगते हैं। इसके अलावा केवी फीस के रूप में कौन कौन से चार्ज लेता है और कितना? किनके लिए पढ़ाई फ्री है?

भारत में केंद्रीय विद्यालयों का अलग ही क्रेज है। देश में केवी की कुल संख्या 1243 है। 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूल विदेश में भी हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े स्कूलों की चेन में से एक है। हजारों सीट हैं। फिर भी ,यड्क की हर क्लास में सीट हमेशा फुल ही मिलती है। हों भी क्यों न? एक तो ये देश के टॉप स्कूलों में गिने जाते हैं। दूसरा केवी की फीस नाम मात्र की ही है। काफी बच्चों के लिए तो ,यड्कस् में पढ़ाई बिल्कुल मुत ही होती है।

आज भी आप सिर्फ 25 रुपये में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं।

एडमिशन फीस के तौर पर आपसे 25 रुपये ही लिए जाते हैं। चाहे आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लें। हर केवी स्कूल का फीस स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही होता है। क्योंकि इसका निर्धारण केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस द्वारा किया जाता है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करती है। हालांकि इन स्कूलों को अपनी फीस निर्धारित करने की छूट भी मिली हुई है।

केवी में किन बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है, इसे लेकर कुछ नियम बदले भी हैं। इसके बारे में आगे बताया गया है।

पहले आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल फीस स्ट्रक्चर समझ लीजिए–

फीस टाइप शुल्क

केवीएस एडमिशन फीस 25 रुपये

केवी री एडमिशन फीस 100 रुपये

केंद्रीय विद्यालय ट्यूशन फीस (प्रति माह)

क्लास 9 और 10 (लड़कों के लिए) 200 रुपये

क्लास 11, 12 (कॉमर्स, आर्ट्स) लड़कों के लिए 300 रुपये

क्लास 11, 12 (साइंस) लड़कों के लिए 400 रुपये

कंप्यूटर फंड

क्लास 3 के बाद 100 रुपये

कंप्यूटर साइंस फीस (क्लास 11, 12 इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए) 150 रुपये

विद्यालय विकास निधि (क्लास 1 से 12 तक) प्रति माह 500 रुपये

केंद्रीय विद्यालय में मुत पढ़ाई का लाभ किन्हें मिलता है?

लड़कियों के लिए केवी में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। 1 से लेकर 12 तक गर्ल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस में एक भी रुपया नहीं देना होता है।

इसके अलावा एससी, एसटी स्टूडेंट्स के लिए केवी ट्यूशन फीस फ्री है।

केवीएस के कर्मचारियों के बच्चों के लिए केवी में पढ़ाई फ्री (ट्यूशन फीस फ्री) है।

ऐसे बच्चे जिनके पैरेंट्स गरीबी रेखा से नीचे (क्यक्कर) हैं और जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं। (दो बच्चों को ही ये लाभ मिलेगा)

दिव्यांग बच्चों को मुत शिक्षा मिलती है। (नियम और शर्तें लागू हैं)

पैरा मिलिट्री और भारतीय सेना के जवानों के लिए भी कई नियम हैं। अलग–अलग नियमों के तहत उनके बच्चों को केवीएस में मुत पढ़ाई का लाभ मिलता है।

फीस में छूट को लेकर जारी सर्कुलर में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों (केवी स्टाफ समेत) को कई तरह की केवी की फीस में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे अपने विभागों से इसके लिए रीइंबर्समेंट (भुगतान) ले लेते हैं।

lh,, dk Qly Q,el D;k g\ tku yhft, ukxfjdrk dkuu ij lokyk d tokc

देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार, 11 मार्च की शाम सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

दिसंबर 2019 में जो कानून तगड़े विरोध के बीच संसद में पास हुआ था, उसे अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है। जिन्हें भारत की नगरिकता चाहिए, उनके अलावा देश के हर नागरिक के लिए सिटिजनशिप अमेंटमेंड एक्ट के बारे में जानना जरूरी है।

खासकर अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिटिजनशिप अमेंटमेंड एक्ट अपनी पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। यहां ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं जो सीएए के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। हर सवाल के साथ उनके जवाब भी दिए गए हैं।

सवाल– सिटिजनशिप अमेंटमेंड एक्ट क्या है?

जवाब– सिटिजनशिप अमेंटमेंड एक्ट। हिन्दी में– नागरिकता संशोधन कानून।

सवाल– सीएए नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? सीएए कानून कब लागू हुआ?

जवाब –11 मार्च 2024

सवाल– सिटिजनशिप अमेंटमेंड एक्ट में किन देशों के किन धर्मों के लोगा. ॅ को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है?

जवाब– बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को सीएए के जरिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

सवाल'– सीएए के लिए अप्लाई कैसे करना है?

जवाब– जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन तरीके से कुछ भी नहीं होगा।

नोट- आप का सामना की हेल्थ,युवा, शिक्षा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते है। आप का सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी,शिक्षा,जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर,शिक्षक से परामर्श लें।

जो कौम अपना इतिहास नही जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नही बना सकती है।

–डॉ० भीमराव अंबेडकर

संपादकीय

धर्म का आधार सीएए के अमल में

आम चुनाव की तारीखों के एलान से कुछ ही दिन पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने का सरकार का फैसला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा चुनाव अभियान के दौरान ध्रुवीकरण के एक मुद्दे का फायदा उठाने की एक पूर्वसूचना मालूम पड़ता है। बतौर तीन चुने हुए देशों के आप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए धर्म–आधारित परीक्षण शुरू करने के एक कानून, सीएए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कानूनी चुनौती के अधीन है। इस कानून का कई लोगों, खासकर मुस्लिम समुदाय, ने कड़ा विरोध किया है। वर्ष 2019 में पारित, इस कानून को अब तक लागू इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सरकार ने इसके प्रावधानों को लागू करने के नियमों को अधिसूचित नहीं किया था। नियमों को अधिसूचित करने का समय इस बात का एक वाजिब संदेह पैदा करता है कि यह कहीं चुनावी बॉन्ड विवाद से ध्यान हटाने का एक प्रयास तो नहीं है। इन नियमों को एक ऐसे समय में पेश किया गया जब देश चुनावी बॉन्ड के गुमनाम खरीदारों और उन्हें भुनाने वाली पार्टियों से जुड़े विवरण जमा करने में की जा रही देरी पर सवाल उठा रहा था। हालात एक ऐसे कानून को लागू करने की तत्काल जरुरत पर सवाल उठाते हैं जिस पर पांच सालों से अमल ही नहीं किया गया है। नए नियम सावधानीपूर्वक तैयार किए गए भी जान पड़ते हैं, क्योंकि वे ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो राज्यों के लिए इसके अमल में बाधा डालने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। यह संभव है कि इन नियमों काफी समय से तैयार रखा गया हो और चुनावी फायदे के लिए सीएए मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है।

सीएए का सार, असल में, अल्पसंख्यक नागरिकों के हितों को प्रभावित नहीं कर सकता हैरू आखिरकार, यह सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों – के लिए नागरिकता हासिल करने का एक श्फास्ट–ट्रैकिंग्य तंत्र है। सामान्य तौर पर 11 सालों (पिछले 14 सालों में से) के बजाय, आप्रवासियों के इस वर्ग के लिए प्रतीक्षा अवधि सिर्फ पांच सालों की होगी, बशर्ते वे 31 दिसंबर, 2014 से पहले आए हों। इसके अलावा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी की नागरिकता को खत्म कर दे। सीएए के साथ समस्या दोतरफा हैरू पहली दिक्कत इसके उस भेदभावपूर्ण मानदंड में है, जो कुछ धार्मिक समुदायों को नागरिकता के पात्र के रूप में निर्दिष्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि इन तीन देशों के इन छह धर्मों के लोग उत्पीडन के चलते भागकर आए हैं। अन्य जो लोग या तो कट– ऑफ तिथि के बाद देश में प्रवेश करने या फिर अपने धर्म की वजह से इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता रहेगा। दूसरा पहलू वह दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक दुष्प्रचार है जिसमें सीएए को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोडने की मांग की गई। इस बयानबाजी ने मुसलमानों के इस डर को बढ़ा दिया कि सीएए की वजह से पर्याप्त दस्तावेजी सबूत के अभाव में नागरिकता खोना पड़ सकता है। अपनी सामग्री (कंटेंट) से ज्यादा, सीएए नरेन्द्र मोदी निजाम द्वारा इस राजनीतिक संदेश के लिए इस्तेमाल के जरिए से नुकसान पहुंचा रहा है कि उसकी सभी नीतियों में धर्म का आधार निहित होगा।

बाइडेन-ट्रम्प की दोबारा भिड़ंत

वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन हासिल करने की दौड़ से दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली के बाहर होने के साथ ही, देश अब मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रतिद्वंद्वी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच 2020 की तर्ज पर दोबारा भिड़ंत देखने के लिए तैयार है। इसमें शायद ही कोई अचरज की बात है कि मुकाबला एक बार फिर इन्हीं दोनों चिर–प्रतिद्वंद्वियों के बीच सिमट गया है। खासकर, यह देखते हुए कि यही वो दो नेता हैं जिन्होंने कई महीनों के प्रचार अभियान के दौरान अपनी–अपनी पार्टियों के भीतर सक्षम उम्मीदवार के तौर पर उभरे। जहां तक रिपब्लिकन खेमे का सवाल है, सुश्री हेली ने संभवतरू उन चंद लोगों की उम्मीदों को मुखरित किया जो रिपब्लिकन पार्टी की मुख्यधारा के रूढ़िवादी मूल्यों के पक्षधर हैं और श्री ट्रम्प एवं उनकी देशी–लोकलुभावन शैली वाली राजनीति की अभूतपूर्व चुनौती से जूझ रहे हैं। फिर भी, प्राइमरी और कॉकस में मतदाताओं का स्पष्ट झुकाव श्री ट्रम्प की ओर शायद इस धारणा के तहत था कि ओवल कार्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान श्अमेरिका को फिर से महान बनानेय का उनका राजनीतिक एजेंडा अधूरा छूट गया था। उधर डेमोक्रेटिक खेमे में, 81 साल की उम्र में, श्री बाइडेन की फिर से राष्ट्रपति पद के कठिन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को लेकर पार्टी के वफादारों के बीच भी एक सवाल बना हुआ है। फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी की दीर्घकालिक संभावनाओं के लिहाज से ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि उनके बीच राष्ट्रीय कद एवं पर्याप्त करिश्मा वाला कोई और दूसरा ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो पार्टी को एक ऐसे चुनाव में पार लगा सके जिसमें श्री ट्रम्प जैसे प्रतिद्वंद्वी की चुनौती सामने है।

अब जबकि सर्वेक्षणों में श्री ट्रम्प को श्री बाइडेन के मुकाबले मजबूत बढ़त मिली हुई है, चुनाव चक्र के इस मुकाम पर इन दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच राजनी. तिक भिड़ंत का नतीजा मतदान के प्रतिशत, रूख पलटने की क्षमता रखने वाले (स्विंग) राज्यों में स्वतंत्र मतदाताओं की प्राथमिकताओं और श्री ट्रम्प के खिलाफ दायर विभिन्न कानूनी मामलों का उनकी प्रचार और मतदाताओं को यह समझाने की क्षमता पर पडने वाले असर कि वह डेमोक्रेटों की साजिशों के शिकार हैं जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। दोनों दलों में इन दो मौजूदा प्रतिस्पर्धियों के अलावा वैकल्पिक नेतृत्व के अभाव से यह पता चलता है कि अमेरिका में राजनीति पक्षपातपूर्ण गतिरोध की पहले से जारी स्थितियों से आगे नहीं बढ़ पाई है।

गठबंधन टूटना तो नियति थी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का गठबंधन टूटना निश्चित हो चुका था क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों ने अपने परस्पर विरोधी जनाधारों को गोलबंद करने के प्रयास तेज कर दिये थे। मुख्यतः खेतिहर जाट समुदाय से जनाधार हासिल करने वाली जेजेपी से अपने रिश्ते तोड़कर, भाजपा एक बार फिर हरियाणा में जाटों और गैर–जाटों की चुनावी द्वंद्वात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जेजेपी के साथ चुनाव में उतरने से भाजपा के लिए राज्य में श्गैर–जाट्य हितों का पसंदीदा वाहक बना रह पाना मुश्किल हो सकता था। भाजपा नेताओं ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया कि भाजपा–जेजेपी गठबंधन वैचारिक बुनियाद पर नहीं, बल्कि केवल सरकार गठन के लिए बना था, और यह चुनाव लडने के लिए नहीं था। भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से आते हैं। लगभग साढ़े नौ साल तक मुख्यमंत्री रहे खट्टर को हटाकर, भाजपा यह भी उम्मीद कर रही है कि वह इसके जरिए 2024 में चुनावों से पूर्व, पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के लिए, श्सत्तारूढ़ दल–विरा. धी भावनाय से निपट पायेगी। कुरुक्षेत्र के सांसद और भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सैनी की नियुक्ति के साथ, पार्टी का लक्ष्य उत्तरी हरियाणा के जिलों में राजनीतिक आधार मजबूत करना है जहां गैर–जाट अपेक्षा.त ज्यादा प्रभाव रखते हैं।

साल 2016 में हरियाणा में जाटों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन हुआ, जिसने इस समुदाय को बाकी सभी के खिलाफ बना दिया, जिसका असर राज्य की राजनीति में अब भी महसूस किया जाता है।

लगभग 36 जातियों से राज्य की विविधतापूर्ण सामाजिक तस्वीर निर्मित होती है और सैनी, बनिया, ब्राह्मण, यादव और पंजाबी उनमें शामिल हैं जो जाट हितों के साथ खड़ी पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जाट राज्य की आबादी का 25 फीसदी हैं और इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) से टूटकर बनी जेजेपी इस समुदाय के मुख्य मंच के रूप में उभरी है। जाटों का राज्य की कांग्रेस में भी खासा प्रभाव है। जेजेपी ने 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा–विरोध को मुद्दा बनाकर लड़ा था, लेकिन 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के बहुमत से चूकने पर, भाजपा और जेजेपी ने सरकार गठन के लिए मौकापरस्त गठबंधन बनाया।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीती थीं, जबकि जेजेपी के पास 10 विधायक थे। यह गठबंधन टूटने के बाद भी भाजपा के पास संख्याबल है।

पार्टी के आत्मविश्वास के दावे के बावजूद, हरियाणा में अचानक से उठाये गये कदम दिखाते हैं कि भाजपा के पास लोकसभा चुनाव से पहले चिंतित होने की वजहें हैं। श्रीफ राजनीतिक पद की मलाई में हिस्सेदारी की ख्वाहिश से, छोटी अवधि के लिए, चलाये जा सकने वाले चुनाव के बाद के रिश्तों के उलट, चुनाव–पूर्व गठबंधनों के लिए वैचारिक समानता और मूल्यों की एकरूपता की जरूरत होती है।

खुदरा मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़े

खुदरा मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़ों ने, एक बार फिर, इस तथ्य को रेखांकित किया है कि कैसे खाद्य पदार्थों की अस्थिर कीमतें न सिर्फ व्यापक मुद्रास्फीति, बल्कि आर्थिक विकास की धुरी यानी व्यक्तिगत उपभोग को भी बंधक बनाए हुए हैं। फरवरी महीने की हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित रीडिंग पिछले महीने के मुकाबले जहां लगभग अपरिवर्तित रहकर 5.09 फीसदी पर टिकी रही, वहीं उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना की गई खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि की रतार 36 आधार अंक बढ़कर 8.66 फीसदी हो गई।

सब्जियों की कीमतें सबसे बड़ी चिंता का सबब बनी हुई हैं। सीपीआई के खाद्य एवं पेय पदार्थ उप–समूह में तीसरी सबसे भारी खाद्य श्रेणी मानी जाने वाली सब्जियों की कीमतों में साल–दर–साल के आधार पर 30.3 फीसदी की मुद्रास्फीति दर्ज की गई है, जोकि जनवरी की रीडिंग के मुक. ाबले चिंताजनक रूप से 315 आधार अंक की तेजी है। और सीपीआई में खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ा भार माने जाने वाले अनाजों की मुद्रास्फीति भी 7.6 फीसदी के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जोकि पिछले महीने की 7.83 फीसदी की रतार से थोड़ी धीमी है। सब्जियों में, आलू–प्याज–टमाटर की तिकड़ी ने इस तेजी की अगुवाई की। सब्जियों की यह तिकड़ी देश भर में सबसे अधिक खाया जाने वाला समूह है और खाद्य श्रेणी में कुल भार का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा रखती है।

जनवरी में आलू की कीमतें जहां साल–दर–साल के आधार पर लगभग दो फीसदी की अपस्फीति से बढ़कर 12.4 फीसदी की मुद्रास्फीति पर पहुंच गईं, वहीं प्याज में 22.1 फीसदी की मुद्रास्फीति दर्ज की गई और टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी करीब 400 आधार अंक के इजाफे के साथ छह महीने के उच्चतम स्तर 42 फीसदी पर पहुंच गई।

उपभोक्ता कार्य विभाग के दैनिक मूल्य निगरानी डैशबोर्ड पर एक नजर डालने पर इस मोर्चे पर हल्की राहत दिखाई देती है। आलू, प्याज और टमाटर की औसत खुदरा कीमतें एक साल पहले के स्तर से 14 मार्च तक क्रमशः 21.3 फीसदी, 41.4 फीसदी और 35.2 फीसदी ज्यादा हैं।

साफ है कि, प्याज के निर्यात पर तीन महीने के प्रतिबंध सहित सरकार के आपूर्ति पक्ष से जुड़े उपायों का इन राजनीतिक रूप से संवेदनशील खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने के लिहाज से बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। और इस संदर्भ में अनुमान भी बहुत ज्यादा आश्वस्त करने वाला नहीं है। बीते 7 मार्च को जारी .षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2023–24 के बागवानी फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 15. 6 फीसदी कम हुआ है और आलू के उत्पादन में लगभग दो फीसदी की कमी का अनुमान है। केंद्रीय जल आयोग का जल भंडारण संबंधी आंकड़ा भी ग्रीष्म ॠतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। यह आंकड़ा 14 मार्च को देश भर के 150 जलाशयों में वास्तविक भंडारण (लाइव स्टोरेज) को कुल क्षमता के 40 फीसदी पर दिखा रहा है और यह 10 साल के औसत एवं एक साल पहले के स्तर, दोनों ही लिहाज से कम पड़ रहा है। यह स्थिति खासतौर से दक्षिणी क्षेत्र में है, जहां 10–वर्षीय औसत के मुकाबले भंडारण घाटा सबसे गंभीर 29 फीसदी के स्तर पर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने पिछले महीने मौद्रिक नीति समिति को दिए अपने बयान में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से पैदा होने वाले अर्थव्यवस्था के जोखिमों के बारे में संक्षेप में बताते हुए कहा थारू षनिजी उपभोग, जो सकल घरेलू उत्पाद का 57 फीसदी हिस्सा होता है, अभी भी बढ़े हुए खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में कम हो रहा है। यह बात खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है। विकास को समावेशी और सतत बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को उसके लक्ष्य तक सीमित रखना होगा। अब जबकि देश में चुनाव होने वाले हैं, अगर अर्थव्यवस्था को असंतोष की गर्मी से बचाना है तो नीति निर्माताओं को अपने काम में पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी।

टीडीपी का एनडीए में लौटना

एक विमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और नयी दिल्ली में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पूर्व संयोजक व आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का दोबारा स्वागत करने के साथ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आंध्र प्रदेश में एक बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 0.84 फीसदी मत पाने वाली भाजपा राज्य में किसी गिनती में नहीं थी। उसे एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा गया जो विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) और पांच साल बढ़ाने के वादे से मुकर गयी। हालांकि कई लोगों ने 2019 के चुनाव से चंद महीने पहले टीडीपी के एनडीए से बाहर निकलने को देर से उठाया गया अपर्याप्त कदम माना, लेकिन राज्य के साथ श्विश्वासघातय के लिए गठबंधन के खिलाफ व्यापक असंतोष को देखते हुए, टीडीपी ने अपने बूते लडने के बावजूद 40 फीसदी मत हासिल किये, अलबत्ता विधानसभा की 175 में से 23 सीटों पर ही उसे जीत मिली। अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण की जन सेना पार्टी (जेएसपी) ने छह फीसदी मत प्राप्त किये और एक सीट जीती, लेकिन भाजपा 175 में से 173 सीटों पर अपने बूते लड़ी और खाली हाथ रही। पांच–कोणीय मुकाबले ने युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी), और उसके नेता वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को शानदार 50 फीसदी मत और विधानसभा में 151 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल करने में कामयाब बनाया।

हालांकि जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन वाई.एस. शर्मिला के वाईएसआरसीपी से बाहर निकलने से कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है और यह मुख्यमंत्री की दुखती रग बन गया है, लेकिन टीडीपी अब भी मुख्य विपक्ष है।

पांच बार लखनऊ लोकसभा जीतकर अटल बिहारी ने रचा इतिहास, एक बार निर्दलीय ने भी दर्ज की जीत

y[kuÅA प्रदेश में भले ही शासन करने वाले राजनैतिक दल बदलते रहे हों, पर लोकसभा चुनाव में राजधानी में कांग्रेस और भाजपा का वर्चस्व रहा है। इस वर्चस्व के बावजूद लखनऊ की संसदीय सीट पर वर्ष 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत का डंका बजा।

उस समय आनंद नारायण मुल्ला ने कांग्रेस के वीआर मोहन को आसानी से मात दी थी।

आनंद नारायण मुल्ला कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके पिता जगत नारायण मुल्ला मशहूर सरकारी वकील थे। आनंद नारायण वकालत करने के साथ ही उर्दू के कवि भी थे। उनकी रचनाआ. ें पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

वर्ष 1967 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया। देश में उस समय कांग्रेस की लहर चल रही थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर उनकी लो. कप्रियता चरम पर थी। इसी के बूते वे चुनाव में खड़े हो गए। चुनाव में कांग्रेस से उनके मुकाबले वेद रत्न मोहन मैदान में उतरे।

वेद रत्न मोहन लखनऊ के पूर्व मेयर रह चुके थे तथा साधन–संपन्नता में भी कोई कमी नहीं थी।

भारतीय जनसंघ से चुनाव में आरसी शर्मा को टिकट मिला था। रिजल्ट की घोषणा हुई तो पहले स्थान पर आनंद नारायण मुल्ला रहे और उन्हें 92,535 वोट मिले। दूसरे नंबर पर वेद रत्न मोहन थे, और उनके खाते में 71,563 वोट आए। वहीं आरसी शर्मा को 60,291 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे।

जगदीश गांधी भी थे मैदान में

इस चुनाव में एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का नाम भी चर्चा में था। सिटी मांटेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 9449 मत मिले।

अलीगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव जीत चुके जगद. ीश गांधी ने इससे पहले वर्ष 1962 का लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उस बार भी उनको हार झेलनी पड़ी। चुनाव में 14774 वोट के साथ वे तीसरे नंबर पर रहे।

जानिए कब कौन जीता

1951– विजय लक्ष्मी पंडित– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1957– पुलिन बिहारी बनर्जी– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1962– बीके धवन– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1967– आनंद नारायण मुल्ला– निर्दलीय

1971– शीला कौल– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1977– हेमवती नंदन बहुगुणा– भारतीय लोकदल

1980– शीला कौल– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1984– शीला कौल– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1989– मांधाता सिंह– जनता दल

1991– अटल बिहारी वाजपेयी– भाजपा

1996– अटल बिहारी वाजपेयी– भाजपा

1998– अटल बिहारी वाजपेयी– भाजपा

1999– अटल बिहारी वाजपेयी– भाजपा

2004– अटल बिहारी वाजपेयी– भाजपा

2009– लालजी टंडन– भाजपा

2014– राजनाथ सिंह– भाजपा

2019– राजनाथ सिंह– भाजपा

सपा में वापस लौटने का सवाल नहीं उठता, किसी पार्टी में विलय के लिए नहीं बनाया दल : स्वामी प्रसाद

jk;cjsyhA राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जमकर कोसा और कहा कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। स्वामी ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने की बात कही है। कहा कि पार्टी किसी दल में विलय की नहीं बनाई गई है, बल्कि उसकी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सपा में वापस जाने की बात से साफ मना किया।

भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और ईडी के माध्यम से व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई है। सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन किसानों को लाभ तो पहुंचा नहीं, बल्कि उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए। उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया।

भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी पार्टी का दर्जा देने के बाद स्वामी ने कहा कि मेरी पार्टी का समर्थन इंडिया एलाइंस को है, क्योंकि किसी भी कीमत पर भाजपा को हराना है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजा. ति का आरक्षण खत्म कर रही है। संविधान विरोधी काम कर रही है। ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और लाभ के संस्थान जैसे एलआईसी, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन इन सभी को निजी हाथों में दे दिया है।

भाजपा से देश को खतरा है इसलिए सत्ता से भाजपा को हटाने का काम करना है।

सपा में दोबारा जाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने खुद पार्टी बनाई है तो अब पार्टी में जाने का सवाल नहीं होता है।

रायबरेली से चुनाव लडने पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी उतरेगा, उसको उनका समर्थन रहेगा और जो भी नाम होगा रायबरेली से वह चौंकाने वाला होगा।

38 में से 12 जिले सबसे अधिक प्रभावित वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों का नए सिरे से वर्गीकरण

ubZ fnYyhA वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के प्रभावित जिलो. का नया वर्गीकरण गृह मंत्रालय ने जारी किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में कुल 38 जिलों को 1 अप्रैल, 2024 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है, जबकि 2015 में यह संख्या 75 थी।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों का नया वर्गीकरण

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का वर्गीकरण 2015 में अनुमोदित राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत संसाधनों की तैनाती के लिए आधार प्रदान करता है।

समस्या से निपटने के लिए किया गया वर्गीकरण

गौरतलब है कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरक. ारें मिलकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ अभी भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 15 जिलों के साथ चार्ट में शीर्ष पर है, इसके बाद ओडिशा (सात जिले), झारखंड (पांच), मध्य प्रदेश (तीन), केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना (दो–दो) और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश (एक–एक) हैं।

कई जिलों को किया गया वर्गीकृत

इनमें से 12 जिले, छत्तीसगढ़ के सात, ओडिशा के दो और झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक–एक जिले को सबसे अधिक प्रभावित जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ओडिशा के दो और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के एक–एक जिले को सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कई जिलों में वामपंथी उग्रवाद का समर्थन

अधिकारियों ने कहा कि इन जिलों में वामपंथी उग्रवाद को समर्थन है। इसलिए, स्थिति को मजबूत करने और कुछ और समय के लिए सुरक्षा और विकास उपायों के संबंध में समर्थन जारी रखने के लिए सहयोग देने की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की बढ़ती स्थिति के कारण जिलों की समय–समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है।

सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मांगा सभी देशों का समर्थन, एआई पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर मतदान

okf'kxVuA संयुक्त राष्ट्र महासभा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर मतदान के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे, मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित, संरक्षित व भरोसेमंद साबित हो। इस प्रस्ताव का प्रायोजक अमेरिका है।

उसने कहा, उम्मीद है कि विश्व निकाय इसे आम सहमति से अपनाएगा और यूएन के सभी 193 देश इसका समर्थन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने कहा कि यदि प्रस्ताव अपनाया गया तो यह एआई के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

उन्होंने कहा, यह संकल्प एआई के विकास–इस्तेमाल में सिद्धांतों के आधारभूत सेट के लिए वैश्विक समर्थन का प्रतिनिधित्व करेगा। यह जोखिमों का प्रबंधन करते हुए एआई सिस्टम का लाभ उठाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य अमीर विकसित देशों और गरीब विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को खत्म करना है और यह सुनिश्चित करना है कि एआई पर चर्चा में वे सभी शामिल हों। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विकासशील देशों के पास एआई का लाभ उठाने के लिए तकनीक और क्षमताएं हों, ताकि बीमा. रियों का पता लगाना, बाढ़ की भविष्यवाणी करना, किसानों व श्रमिकों की मदद आसान हो सके।

एआई एक उभरता क्षेत्र

अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र में लाया जाने वाला प्रस्ताव एआई विकास व उपयोग में तेजी को मान्यता देता है। साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद एआई प्रणालियों पर वैश्विक सहमति की तात्कालिकता पर जोर देता है। यह मानता है कि एआई प्रणालियों का शासन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके लिए संभावित शासन .ष्टिकोण पर और चर्चा की आवश्यकता है। मसौदे में एआई को विनियमित करने की जरूरत का समर्थन किया है।

वैश्विक चर्चा के लिए महासभा का रुख किया

यूरोपीय संघ के सांसदों ने 13 मार्च को दुनिया के पहले व्यापक एआई नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो कुछ अंतिम औपचारिकताओं के बाद मई या या जूने तक प्रभावी हो जाएंगी। अमेरिका और चीन सहित दुनिया भर के देश तथा 20 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह भी एआई नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी एनएसए ने बताया कि अमेरिका ने एआई की तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रौद्योगिकी के निहितार्थों को प्रबंधित करने के तरीके पर वास्तव में वैश्विक बातचीत करने के लिए महासभा का रुख किया है।

2030 तक विकास लक्ष्यों में एआई का इस्तेमाल

मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, इसका प्रमुख लक्ष्य 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बुरी तरह से पिछड़े विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के लिए एआई का इस्तेमाल करना है। इसमें वैश्विक भूख और गरीबी को खत्म करना, दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार करना, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना और लैंगिक समानता हासिल करना शामिल है।

पाकिस्तान आतंकवाद के भयानक खतरे का सामना कर रहा : डोनाल्ड लू

o,f'kxVuA बाइडन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा बढने को लेकर चिंता जताई है। वहीं, एक अमेरिका के सांसद ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से कार्रवाई की मांग करते हुए आरा. ेप लगाया है कि भारत से आयातित झींगा बंधुआ मजदूरी पर निर्भर है और यह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।

40 साल से संघर्ष जारी

सदन में बुधवार को पाकिस्तानी चुनावों पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद के भयानक खतरे का सामना कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी सीमा से लगे इलाकों में आतंकवादी गति. विधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल से संघर्ष जारी है। इसमें पाकिस्तान फंस कर रह गया है।

लू ने कहा, श्अफगानिस्तान में युद्ध खत्म होना हम सभी को पाकिस्तान के साथ उसकी अपनी शर्तों पर संबंध रखने का अवसर देती है और हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा, हमारा अब एक बड़ा लक्ष्य है पाकिस्तानी लोगों की मदद करना क्योंकि वे आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। यह एक ऐसा देश है, जहां लोग आतंकवाद के खतरे से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी देश को ऐसे आतंकवाद को नहीं सहना पड़ा है– जैसे पाकिस्तान के लोग सह रहे हैं। कई सदस्यों ने इस पर चर्चा की है।

अफगानिस्तान से हमले जारी

लू ने कहा कि पिछले तीन सालों में अफगानिस्तान से हमले जारी हैं। विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में हमले तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने आगे कहा, शनिवार को ही एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें सात पुलिसकर्मी मारे गए। हम अफगान तालिबान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि उसकी भूमि का इस्तेमाल आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए न हो।

भारत से आयातित झींगा बंधुआ मजदूरी पर निर्भर

अमेरिका के सांसद बिल कैसिडी ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) से कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया है कि भारत से आयातित झींगा बंधुआ मजदूरी पर निर्भर है और यह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आउटलॉ ओशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी होने के बाद सांसद ने व्यापार प्रतिनिधि से अनुरोध किया।

स्वामी,सम्पादक,प्रकाशक व मुद्रकः संतोष कुमार शुष्टा, आकाश व्यू, छकड़ायल रोड, कमला नगर, संजौली शिमला हि0 प्र0 – 171006 से प्रकाशित तथा सिग्मा प्रिंटर ब्लॉक न.6,शॉप न.170 एसडीए कॉम्पलेक्स कसुम्पटी शिमला से मुद्रित। किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र शिमला ही मान्य होगा। मोबाईलः 09418453928,9805192400 e-mail: aapkasaamna@gmail.com